



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

अस/धारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 66] नई दिल्ली, बुध्स्पतिवार, फरवरी 29, 1968/फाल्गुन 10, 1889  
No 66] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 29, 1968/PHALGUNA 10, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय  
(अर्थ विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 1968.

एस० एन० 811.—सांविधिक आदेश: राष्ट्रपति का निम्नलिखित आदेश सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है।

आदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 और वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33वां) के उपबन्धों के अनुसरण में, राष्ट्रपति ने 15 मार्च, 1968 से वित्त आयोग नियुक्त किया है जिसके अध्यक्ष भूतपूर्व पुनर्वास मंत्री, श्री महावीर त्यागी होंगे और चार अन्य सदस्य होंगे, जिनके नाम ये हैं: :

1. श्री पी० सी० भट्टाचार्य, भूतपूर्व गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक
2. श्री एम० शेषाचलपति, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
3. डा० डी० टी० लकड़ावाला, प्रोफेसर, अर्थ-शास्त्र विभाग, बम्बई विश्वविद्यालय
4. श्री बी० एल० गिडवानी, भूतपूर्व मुख्य सचिव, गुजरात सरकार, सदस्य-सचिव।

2. आयोग के सदस्य 31 जुलाई 1969 तक अपने पदों पर बने रहेंगे।

3. श्री महावीर त्यागी आयोग के अध्यक्ष के रूप में उस तारीख तक, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित की जायगी, अंश-कालिक रूप से काम करेंगे और उस के बाद आयोग के अध्यक्ष के रूप में पूर्ण कालिक रूप से काम करेंगे। अन्य सदस्यों में श्री पी० सी० भट्टाचार्य उस तारीख तक, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित की जायगी, आयोग के सदस्य के रूप में अंशकालिक रूप से काम करेंगे और उसके बाद आयोग के सदस्य के रूप में पूर्णकालिक रूप से काम करेंगे। अन्य तीन सदस्य पूर्णकालिक रूप से काम करेंगे।

4. आयोग निम्नलिखित विषयों के बारे में सिफारिशें करेगा :—

- (क) संघ और राज्यों के बीच उन करों, जो वसूल की जाने वाली शुद्ध रकमों का बटवारा, जो संविधान के भाग XII के अध्याय I के अनुसार उनके बीच बांटे जाने होते हैं या बांटे जा सकते हैं, और वसूल हुई इन रकमों में प्रत्येक राज्य के हिस्से का निर्धारण ;
- (ख) वे सिद्धान्त, जिनके आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को उनके राजस्व के सहायक अनुदान दिये जाने चाहियें और संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (I) में निर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न और पंचवर्षीय आयोजना की आवश्यकताओं से भिन्न प्रयोजनों के लिए उन राज्यों को दी जाने वाली धनराशि, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत उन के राजस्व के सहायक अनुदानों के रूप से सहायता की जरूरत है। इन के सम्बन्ध में सिफारिशें करते हुए अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित बातों का ध्यान भी रखा जाना चाहिए :—
  - (i) उन राज्यों में 1968-69 के वित्तीय वर्ष के अन्त में कराधान के सम्भाव्य स्तर पर आधारित, उन राज्यों के 1973-74 के वित्तीय वर्ष के अन्त में समाप्त होने वाले पांच वर्षों के लिए राजस्व-साधन ;
  - (ii) प्रशासन, ऋण के व्याज, 1968-69 के अन्त तक पूरी होने वाली आयोजनागत योजनाओं के रख-रखाव, स्थानीय निकायों और सहायता प्राप्त संस्थाओं को धन के अन्तरण सम्बन्धी खर्च और अन्य वचन बद्ध व्यय को पूरा करने के लिए उन राज्यों की राजस्व खालों की आवश्यकताएं ;
  - (iii) राज्यों द्वारा, कार्य कुशलता को बनाये रखते हुये, अपने प्रशासनिक व्यय, रख-रखाव और विकास सम्बन्धी व्यय तथा अन्य खर्चों में की जा सकने वाली किराया और राजस्व के पहले से बेहतर प्रबन्ध की गुंजाइश ;
- (ग) रेल यात्री किराया कर के स्थान पर, जो समाप्त कर दिया गया है, राज्यों को दिये जाने वाले अनुदान के राज्यों के बीच बंटवारे के सिद्धान्तों में किये जाने वाले कोई परिवर्तन ;
- (घ) कृषि-भूमि से भिन्न सम्पत्ति सम्बन्धी मृत-सम्पत्ति शुल्क (एस्टेट ड्यूटी) की किसी वित्तीय वर्ष में वसूल शुद्ध (नेट) रकमों के, संविधान के अनुच्छेद 269 के अन्तर्गत राज्यों में बंटवारे के सिद्धान्तों में किये जाने वाले कोई परिवर्तन ;
- (ङ) चीनी, कपड़े, और तम्बाकू पर राज्यों के बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क लगाये जाने से सम्बन्धित अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत मौजूदा प्रबन्ध को संशोधन

सहित अथवा संशोधन के बिना बनाये रखने की वांछनीयता अथवा अवांछनीयता और इस प्रबन्ध को प्रम्य मर्जों, या वस्तुओं पर लागू करने की गुंजाइश ;

- (च) उपर्युक्त मद (ङ) के अन्तर्गत की जाने वाली सिफारिशों पर विचार किये बिना निम्नलिखित वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु पर राज्यों के बीक्री करों, के स्थान पर, जो पहले राज्य सरकारों द्वारा लगाये जाते थे, 1957 के उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत लगाये जाने वाले अतिरिक्त उत्पादन-शुल्कों की किसी वित्तीय वर्ष में वसूल शुद्ध रकमों के बंटवारे के सिद्धान्तों में किये जाने वाले कोई परिवर्तन,

- (i) सूती कपड़ा,
- (ii) रेशमी कपड़ा,
- (iii) ऊनी कपड़ा,
- (iv) रेयन अथवा नकली रेशम का कपड़ा,
- (v) चीनी, और
- (vi) निर्मित तम्बाकू सहित तम्बाकू,

लेकिन शर्त यह है कि प्रत्येक राज्य को मिलने वाला हिस्सा उस राज्य को 1956-57 के वित्तीय वर्ष में विक्री कर लगाये जाने से वसूल राजस्व से कम नहीं होगा ;

(छ) मद (ङ) के अन्तर्गत, राज्यों के विक्री करों के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाये जाने के लिये जिन अतिरिक्त मदों या वस्तुओं की सिफारिश की जाय, उन से वसूल होने वाली शुद्ध रकमों के बंटवारे के सिद्धान्त ;

(ज) उन करों और शुल्कों से, जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 269 में किया गया है, लेकिन जिन्हें फिलहाल लागू नहीं किया गया, राजस्व जुटाने की गुंजाइश ;

(झ) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा, उन्हें उपलब्ध राजस्व-स्रोतों से, अतिरिक्त राजस्व जुटाने की गुंजाइश ;

[(ञ) कुछ राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक से जमा से अधिक रकम के अनधिकृत रूप से निकाले जाने की समस्या और इस प्रकार रकम निकाले जाने को रोकने के लिए, पालन की जाने वाली प्रक्रिया ।

5. आयोग उपर्युक्त विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें करते समय, केन्द्रीय सरकार के साधनों और उस पर असेनिक प्रशासन, प्रति-रक्षा और सीमाओं की सुरक्षा, ऋण-परि-शोधन, और अन्य वचन-बद्ध व्यय अथवा देनदारियों के पड़ने वाले बोझ को ध्यान में रखेगा ।

6. आयोग, उपर्युक्त पैरा 4 में उल्लिखित विषयों में से "यथासम्भव अधिक से अधिक विषयों के बारे में और विशेष रूप से 1969-70 के वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में, 30 सितम्बर, 1968 तक एक अन्तरिम रिपोर्ट देगा ; और उपर्युक्त विषयों में से प्रत्येक के सम्बन्ध में, 1 अप्रैल, 1969 से शुरू होने वाले पांच वर्षों के लिए, 31 जुलाई, 1969 तक अन्तिम रिपोर्ट पेश करेगा ; जिस में आयोग द्वारा सम्बद्ध दस्तावेज उपलब्ध करते हुए यह बताया जायेगा कि वह अपने मिष्कषों पर किस आधार पर पहुंचा है ।

जाकिर हुसैन,  
राष्ट्रपति ।

[संख्या 13(1)-बी०/68]  
टी० पी० सिंह, निरक्षर सचिव ।

# MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February 1968

S.O. 812.—The following Order made by the President is published for general information:—

### ORDER

In pursuance of the provisions of article 280 of the Constitution of India and of the Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951 (33 of 1951), the President is pleased to constitute with effect from the 15th March, 1968, a Finance Commission consisting of Shri Mahavir Tyagi, former Union Minister of Rehabilitation, as the Chairman and the following four other members, namely:

1. Shri P. C. Bhattacharyya, former Governor, Reserve Bank of India.
2. Shri M. Seshachalapathy, retired Judge, Andhra Pradesh High Court.
3. D. T. Lakdawala, Professor, Department of Economics, Bombay University.
4. Shri V. L. Gidwani, former Chief Secretary, Government of Gujarat, Member-Secretary.

2. The members of the Commission shall hold Office until the 31st day of July, 1969.

3. Shri Mahavir Tyagi shall render part-time service as Chairman of the Commission until such date as the Central Government may specify in this behalf and thereafter, he shall render whole-time service as Chairman of the Commission. Of the other members, Shri P. C. Bhattacharyya shall render part-time service as member of the Commission until such date as the Central Government may specify in this behalf and thereafter, he shall render whole-time service as member of the Commission. The other three members will render whole-time service.

4. The Commission shall make recommendations as to the following matters:—

- (a) the distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes which are to be, or may be, divided between them under Chapter I of Part XII of the Constitution and the allocation between the States of the respective shares of such proceeds;
- (b) the principles which should govern the grants-in-aid of the revenues of the States out of the Consolidated Fund of India and the sums to be paid to the States which are in need of assistance by way of grants-in-aid of their revenues under article 275 for purposes other than those specified in the provisos to clause (1) of that article and other than the requirements of the Five Year Plan, having regard, among other considerations, to—
  - (i) the revenue resources of those States for the five years ending with the financial year 1973-74 on the basis of the levels of taxation likely to be reached at the end of the financial year 1968-69;
  - (ii) the requirements on revenue account of those States to meet the expenditure on administration, interest charges in respect of their debt, maintenance and upkeep of Plan schemes completed by the end of 1968-69, transfer of funds to local bodies and aided institutions and other committed expenditure;
  - (iii) the scope for better fiscal management as also for economy consistent with efficiency which may be effected by the States in their administrative, maintenance, developmental and other expenditure;
- (c) the changes, if any, to be made in the principles governing the distribution amongst the States of the grant to be made available to the States in lieu of the repealed tax on railway passenger fares;
- (d) the changes, if any, to be made in the principles governing the distribution amongst the States under article 269 of the net proceeds in any financial year of estate duty in respect of property other than agricultural land;

- (e) the desirability or otherwise of maintaining the existing arrangements under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957, in regard to the levy of additional duties of excise on sugar, textiles and tobacco in lieu of the States' sales taxes thereon, with or without any modifications and the scope for extending such arrangements to other items or commodities;
- (f) irrespective of the recommendation made under item (e) above, the changes, if any, to be made in the principles governing the distribution of the net proceeds in any financial year of the additional excise duties leviable under the 1957 Act aforesaid on each of the following commodities, namely,
- (i) cotton fabrics,
  - (ii) silk fabrics,
  - (iii) woollen fabrics,
  - (iv) rayon or artificial silk fabrics,
  - (v) sugar, and
  - (vi) tobacco including manufactured tobacco,

in replacement of the States' sales taxes formerly levied by the State Governments;

Provided that the share accruing to each State shall not be less than the revenue realised from the levy of the sales tax for the financial year 1956-57 in that State.

- (g) the principles which should govern the distribution of the net proceeds of such additional items or commodities as may be recommended under item (e) above for levy of additional excise duties in lieu of the States' sales taxes thereon;
- (h) the scope for raising revenue from the taxes and duties mentioned in article 269 of the Constitution but not levied at present;
- (i) the scope for raising additional revenue by the various State Governments from the sources of revenue available to them; and
- (j) the problem of unauthorised overdrafts of certain States with the Reserve Bank and the procedure to be observed for avoiding such overdrafts.

5. The Commission in making its recommendations on the various matters aforesaid shall have regard to the resources of the Central Government and the demands thereon on account of the expenditure on civil administration, defence and border security, debt servicing and other committed expenditures or liabilities.

6. The Commission shall make an Interim Report by the 30th September, 1968 covering as many of the matters mentioned in para 4 above as possible and in particular, in respect of the financial year 1969-70; and make the final Report by the 31st July, 1969 on each of the said matters and covering a period of five years commencing from the 1st day of April, 1969, indicating in its Reports the basis on which it has arrived at its findings and making available the relevant documents.

ZAKIR HUSAIN,

President.

[No. 13(1)-B/68.]

T. P. SINGH,

Finance Secy.

